उपसभापति : जवाब दे रहे हैं ।

श्री अर्जुन सिंह : मैं जवाब दे रहा हूं । जहां तक उन प्रश्नों का सवाल है जिनको आइडेंटीफाई किया जा चुका है, जिनकी वजह से हमारी कमियां सामने उजागर हुई हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है और उसी प्रयास के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमें आशा है कि अबकि दफा की टीम शायद बेहतर पहले से अपना रंग दिखायेगी ।

Production of pulses and oilseeds

*144. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that pulses and oilseeds are the main source of protein and fat for the masses of the country;

(b) whether it is also a fact that their cultivation, production and consumption are on decline;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps being contemplated to improve their production and consumption?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) Area, production and availability of oilseeds and pulses for the year 1985-86 and 1990-91 are given below:—

	Oilseeds/Edible oil	
	1985-86	1990-92
Area (million hectares	19.02	24.31
Domestic production of oilseeds (million tonnes)	10.83	18.46
Edible oil availability (including availability through imports)—kgs. per capita per annum	5.0	5.40

	PULSES	
	1985-86	1990-91
Area (million hectares)	24.42	24.40
Domestic production of pulses (million tonnes)	13.36	14.06
Availability (including availability through imports) grams per capita per day.	38.40*	41.40*

Between the above years, production of oilseeds increased impressively by 70 per cent though the area under cultivation increased by only 26 per per cent. Per capita availability of edible oil also increased significantly. Production of pulses reached a record figure in 1990-91. Per capita availability of pulses improved in 1990 compared to 1985. However, current per capita availability is much lower than the peak availability of 74.9 grams per capita per day reached in 1959.

(c) The major reasons for declining availability of pulses are:—

(i) Production has not kept pace with the increase in population.

(ii) About 92 per cent of the pulses area is rainfed, where production continues to be very low.

(iii) Lack of genetic breakthrough in pulse varieties as compared to cereals.

(d) To improve the production of oilseeds, a Centrally Sponsored Oilseeds Production Programme (OPP) is under implementation in 21 States. Another Centrally Sponsored Scheme, the National Pulses Development Programme (NPDP) is being implemented in 24 States and two Union Territories. Under these pro-

*Relate to calendar years 1985 and 1990.

grammes, assistance is provided for items like production and distribution of certified seed, plant protection chemicals and equipments, distribution of improved farm implements, sprinkler sets, hryzobium culture. In the case of pulses there is also a Central Sector Scheme Viz. Special Foodgrains Production Programme (SFPP)—Pulses) which provides assistance for plant protection measure on gram and arhar and also assistance of poor widows, destitutes and Haritance for plant protection measures on gram and arhar and also assistance on seed component for summer pulses. Pulses have now been subjected to the Technology Mission approach with special emphasis on population of improved varieties and packages of practices through frontline demonsrations.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : उपसभापति महोदया मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह भ्रामक भी है और निराशाजनक भी है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अाम तौर पर गरीब लोग हैं जो कि दाल-रोटी या दाल-चावल खाकर गुजारा करते हैं। दालों के बारे में और खाने के तेल के बारे में जो आंकड़े यहां दिए गए है, यह मेरे प्रश्न से मेल नहीं खाते। मैंने इतना पूछा था कि इनकी प्रति व्यक्ति कितनी उपलब्धता है, लेकिन मंत्री महोदय ने उपलब्धता के बारे में बताते हुए आयातित दालें और खाने के तेल को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है जोकि मेरे प्रश्न का भाग नहीं था। अब मैं इसमें जो गलत बातें कही गयी है, उनके बारे में मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। उपसभापति महोदया मंत्री महोदय ने एक ही सांस में दो बातें कही हैं कि वर्ष 1990–91 में दालों की सबसे अधिक रिकार्ड एवेलेबिलिटी हुई है, प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि 1990 में एज कंपेअर्ड टू 1985 एवेलेबिलिटी तो बढ़ी है लेकिन 1959 के मुकाबले में यह कम हुई है। इस कमी के संबंध में जो कारण बताए गए है उसमें जनसंख्या का कारण और दूसरे कारण हैं। तो मेरे प्रश्न का "क" भाग यह है कि 1959 से जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हुई है, उसके कारण क्या हैं? क्या उपज में कमी आयी है या जनसंख्या बढ़ जाने के कारण यह परिस्थिति आयी है। यह एक बात है।

उपसभापति : देखिए, मैं आपको एक बात गायडेंस के तौर पर बता दूं कि यह जो भाग "क" "ख" "ग" और "घ" का तरीका है, वह ड्राप कर दीजिए क्योंकि मैं कोशिश यह करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने यहां सवालों के नोटिस दिए हैं और मंत्री महोदय तैयारी कर के आते हैं, उस पर सरकार का और पार्लियामेंट का धन लगता है, इसलिए उन सब लोगों के भी क्यूश्चंस आ सकें।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : आप यह नियम बना दें।

उपसभापति : यह नियम मैंने बना दिया है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : लेकिन मेरे से ही यह नियम शुरू न करें।

उपसभापति : अब कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। I have to take some steps from somewhere.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न करूंगा कि आपने जो एवेलेबिलिटी की बात कही है, मैं यहां यह भी जोड़ना चाहता हूं कि आप उपलब्धता के साथ-साथ यह भी बताएं कि उसके दाम कितने बढ़े हैं और दाम बढ़ने के कारण गरीबों के लिए उपलब्धता में जो कमी आयी है, उसमें इस कारण कितना योगदान है? यह मेरे प्रश्न के "क" और "ख" भाग हैं मंत्री जी इनका जवाब दें, फिर मैं दूसरा सप्लीमेंटरी पूछूंगा।

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसमें दोनों ही प्रश्न पूछे हैं—ऑइल सीड के बारे में और पल्सेज के बारे में भी। अगर दोनों का उत्तर चाहिए तो दोनों का दूंगा, अगर पल्सेस का चाहेंगे तो वही दूंगा। पल्सेस के बारे में हमें जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए था, वह इसलिए नहीं हो पाया

क्योंकि यह सारी खेती सूखे क्षेत्र में होती थी। जितनी खेती दाल की होती थी, वह 92 प्रतिशत सूखे वाले क्षेत्र में होती है। फिर इस की खेती में पैसा ज्यादा नहीं मिलता है और सबसे ज्यादा हमारा ध्यान दूसरी ओर इसलिए आकर्षित होता रहा है कि चावल में, धान में, दूसरी चीजों में किसान को ज्यादा पैसा मिलता है और उनकी आवश्यकता भी थी कि भोजन उपलब्ध कराया जाए। तो जितना ब्रेक थ्रू लेकर हमने उसमें आगे बढ़ने की चेष्टा की उतना इसमें हो नहीं पाया था। इसलिए आपको यह लग रहा है कि इसमें नहीं हुआ है। दूसरे उपसभापति महोदया, जिस तरीके से उत्पत्ति हमारी हुई है कि 34 करोड़ के बजाय 86 करोड़ बैठे हैं, तो उस वजह से यह चीज हो रही है कि उसमें कमी आई है। सन् 1959 में जितनी हमारी जनसंख्या थी, उसके मुकाबले में आज की जनसंख्या का आप अनुपात देख लीजिए, लेकिन जब जिस तरीके से हम विचारकर रहे है इसके लिए हमने सब स्टेट्स को लिखा है, सारे मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि हम आपको पैसा भी दे रहे हैं फिर भी वह पिछले सालों में उस काम में नहीं लगा है। केन्द्र सरकार 75 प्रतिशत देना चाहती है, इस साल 30 करोड़ रुपया रखा है कि आप करो इस काम को और इसकी तरफ ध्यान दो। यह काम करो और किसी तरीके से इसकी अनदेखी मत करो। इसी तरह से हमने ऑइल सीड्स के बारे में कहा है कि इसमें 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और 10 लाख से 18 लाख हुआ है। इसकी पर केपिटा हमारी कंजम्पशन की तादाद भी बढ़ी है, उसी तरीके से इसकी आयात कम हुई है। हमें दाल का आयात करना पड़ा है, सात लाख टन आयात किया है। उस तरीके से जैसे ऑयल सीड का आयात के बजाय निर्यात बढ़ा लिया है, अब इस दफा हमारे ऑयल सीड के निर्यात में 1,046 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आप यह अंदाजा कर सकते हैं कि जिस तरीके से पैसा मिलता है किसान को उसकी तरफ उसका आकर्षण बढ़ता है। इसलिए इसमें हम कोशिश कर रहे है, जितने प्रोग्राम बनाए जा रहे है उसमें सारी बातें है। अगर कहो तो मैं आपको अभी पढ़कर और एक-एक करके बताता हूं कि हम क्या-क्या काम करना चाह रहे हैं, जिससे कि अन्न की उत्पत्ति बढ़े, उसमें हमने किस तरीके से यह पलसेस के लिए, दूसरे काम के लिए भी उनको उन्नत बीज देने के लिए भी, खेती के तरीके बताने के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए भी सूखे के दौरान जो बीज सूखे को बर्दाश्त कर सकें वह देने के लिए भी, सारे हमारे जितने साइंटिस्ट हैं उनको भी यही कह गया है कि नए बीजों की उत्पत्ति करो, जिससे उनका उत्पादन बढ़े, जिससे किसानों का आकर्षण हो। यह सारी बातें ध्यान में रखते हुए हमने किया है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दूसरा प्रश्न जो पूछना चाहता हूं, वह यह कि आम तौर पर यह देखा गया है कि अगर उत्पादकों को प्रोत्साहन न दिया जाए तो वे नई क्रोप-पैटर्न की तरफ या नई वैरायटीज की तरफ नहीं जाते हैं और जो आपने तीन कारण बताए, जिसमें से पलसेस की कम उपज हुई है, उसमें हमने कहा है कि बहुत सारा 92 प्रतिशत एरिया रेनफेड है। अब इतने वर्षों के बाद, इतनी विज्ञान की तरक्की के बाद क्या हम अभी तक इस रेनफेड एरियाज में कोई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जिससे कि यह क्रोप जो है, इसकी उपज ज्यादा हो और किसान को प्रोत्साहन मिले। पहली बात, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन रेनफेड एरियाज में कौनसे ऐसे पग उठाए जा रहे हैं, जिससे कि इन रैनफेड एरियाज में किसानों को और सुविधाएं मिलें, जिससे कि उपज बढ़े? दूसरा मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने कोई टारगेट रखा है कि हम आयात समाप्त करके, यहां के किसानों को इन्सेन्टिव देकर, प्रोत्साहन देकर हम अपने आपको सेल्फ-सफिसिएंट बनाएं, अपने पांव पर किसानों को खड़ा करें, और ऑयल सीड और पलसेस में और आत्मनिर्भर हो जाएं?

श्री बलराम जाखड़ : जैसा आपने कहा है उनको दिशा नहीं देना है, बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार से हम उनको बीज देने की कोशिश करते हैं और कम पानी से उत्पादन हो ऐसे बीज देने की भी कोशिश करते हैं और किस तरीके से जैसे ड्रिप एरीगेशन, या स्प्रिंकलर एरीगेशन का जो प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए अनुदान दे रहे है, सबसिडी दे रहे हैं, उसके

लिए ढेर सारा पैसा इसलिए दे रहे हैं, जहां यह सूखे की खेती होती है थोड़ा पानी भी हो तब भी फसल हो जाए । किसान तभी उत्पादन करेगा, माननीय महामना, जब थोड़ा उसको पैसा मिलेगा और अगर उसमें कम उत्पति होती है, पैसा नहीं मिलगा है तो वह दूसरी खेती में जाएगा, जहां उसको ज्यादा पैसा मिलेगा है । इसलिए नए बीजों का उत्पादन करके, नई इसमें जेनेटिक रिसर्च की जा रही है जिससे कि इनका उत्पादन ज्यादा हो, जिससे किसान इस तरफ आकर्षित हों, जैसे गेहूं में किया, चावल में किया, अब आपने ऑयलसीड में किया । सारा जिस तरीके से किया है, एक तरफ चल पड़े थे, चल पड़े थे, लेकिन अब इसका डायवर्सिफिकेशन करके दालों की तरफ भी जा रहे हैं, जिस तरीके से उससे छुटकारा पा सकें अपने ऑयलसीड की कमी से, उसी तरह से दालों ने भी छुटकारा हो क्योंकि यही प्रोटीन का हमारा साधन है ।

श्री अजीत जोगी : महोदया, तिलहन के क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने, मध्यप्रदेश ने बहुत प्रगति की है और विशेषकर सोयाबीन का उत्पादन अब सबसे अधिक मध्यप्रदेश में हो रहा है इसलिए उसे राष्ट्र का सोयाबीन प्रदेश भी कह रहे हैं । जिन क्षेत्रों में सोयाबीन होता है वहां के किसानों का यह अनुभव है कि यदि उन्हें, बीज, जिस समय लगाया जाता है उसी समय जो बायो फर्टिलाइजर जिसे राइजोबिस कल्चर कहते हैं, उपलब्ध कराया जाय तो उसका उत्पादन डेढ़ से दो गुना बढ़ जाता है । यह प्रश्न मैंने कई बार किया और निवेदन भी कई बार किया है, किन्तु न जाने किन कारणों से हम, यह जो राइजोन कल्चर है, जिन क्षेत्रों में सोयाबीन हो रहा है, वहां के किसानों को उपलब्ध नहीं कर पाते हैं । तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि केवल एक कम खर्च की चीज उपलब्ध करा देने से व जब उत्पादन डेढ़ से दोगुना बढ़ सकता है तो क्यों न योजना बनाकर शासन से बात करके उसे सभी क्षेत्रों में, जहां सोयाबीन लगाया जा रहा है वहां, उपलब्ध कराते हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : बिल्कुल सही बात है और इसके लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है और खास तौर पर मध्य प्रदेश में क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है । 18 लाख टन से भी ज्यादा उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में होता है तथा दूसरे प्रदेशों में थोड़ा होता है । इसके लिए हम पूर्णरूपेण यत्न कर रहे हैं ।

श्री अजीत जोगी : इस साल भी नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिला उनको?

श्री बलराम जाखड़ : मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश केलिए एक नये बीज का भी उन्होंने उत्पादन हुआ थी खोज हुई है जो कि 2400 किलोग्राम तक फी हेक्टेयर में उत्पादन देगा । उसके लिए पूर्णरुपेण चेष्टा करके हम सोयाबीन पैदा करना चाहते हैं।

SHRI SOM PAL: Madam Deputy Chairperson, everyone acknowledges the fact—and statistics also support it—that after the creation of Oil Technology Mission very good progress has been made on the front of oilseeds production in India. But a very disturbing trend has been observed during the last two-three years that a sizable crop area has been shifted to oilseeds from foodgrain crops, particularly wheat, and this has resulted in low production of wheat which has necessitated the import of wheat. Is the Ministry of Agriculture monitoring this trend? What measures are being contemplated to check this phenomenon? This is all I want to know.

SHRI BALRAM JAKHAR: This is not a fact. Wheat production has not been less. This year, we have a very good crop of wheat. You might be minimising the fact... (*Interruptions*)...

SHRI SOM PAL: My first question is shifting of... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is coming to it.

SHRI BALRAM JAKHAR: Naturally, the answer I gave to the hon. Member there, to the first question, applies to this also. Money, profits, a farmer is not averse to that. He is

going to cultivate a crop which gives him money, which gives him profit... (*Interruptions*)...

SHRI SOM PAL: I know the reason, because of good prices...

SHRI BALRAM JAKHAR: Just, wait. ...(*Interruptions*)... Just wait. ...(*Interruptions*)...

उपसभापति : सोमपाल जी, मंत्री जी का जवाब तो आप सुन लीजिए, क्या बोल रहे हैं वह ।

SHRI BALRAM JAKHAR: But it doesn't matter. You see, what we do is to produce more. If we produce something more, we can barter it for something else. There is no harm in it and this is the law of economics. I want my farmers to have more cash in their pockets, I want my farmers more healthy and wealthy and they must progress alongside with others. I don't want that they should only produce what is needed otherwise. They should be paid for what they are doing. They do it all day and night, throughout the year. Why should we grudge about what they produce and what they get for that? So I don't mind; they should produce. Then I can barter it for anything else.

श्री अनन्त राम जायसवाल : फसलों के बारे में कोई ट्रेनिंग है क्या आपकी ?

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : उपसभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उन्होंने ऑयल सीड्स और पल्सेज के आंकड़े दिये हैं, उससे यह साफ होता है कि ऑयल सीड्स का उत्पादन 1985-86 की तुलना में 1990-91 में बढ़ा है । इसका मुख्य कारण यह है कि ऑयल सीड्स के जो दाम हैं, वह सरकार ने बढ़ाये । इसलिए इस देश में ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़ा और पल्सेज के बारे में जब हम देखते हैं, न उनका एरिया बढ़ा है मिलियन हेक्टेयर्स में, न उनका उत्पादन बढ़ा है । हमारे देश में 500 किलोग्राम प्रति हक्टेयर उत्पादन ऑयल सीड्स का है और 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पल्सेज का है । यह दुनियां में सबसे लॉएस्ट है और गरीबों के लिए ऑयल सीड्स, मूंगफली या पल्सेज ऐसी चीजें हैं जिसमें से प्रोटीन्स मिलता है । तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रत्येक हेक्टेयर यील्ड बढ़ाने के लिए हम क्या-क्या उपाय करने जा रहे हैं ? यह मेरा पहला प्रश्न है ।

श्री चतुरानन मिश्र : घड़ी को भी देख लीजिए, जवाब नहीं मिलेगा ।

उपसभापति : दूसरा नहीं, बस एक ही सवाल । मंत्री जी, जवाब दें दे । ...(**व्यवधान**) "बी" नहीं होता, आज से "बी" नहीं है, "ए" ही है । ...(**व्यवधान**) बोलने दीजिए न, जवाब देने का समय नहीं है ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : दूसरे, मैं यह पूछना चाहता हूं कि बॉयो फर्टिलाइजर जो है, उसमें क्या प्रगति हो रही है ?

श्री बलराम जाखड़ : जिससे माननीय सदस्य चिंतित हैं, उससे मैं भी चिंतित हूं और उसी के लिए बहुत सारे काम है । अब समय नहीं रहा, मैं आपको भेज दूंगा । जो प्रयत्न हम कर रहे हैं, जो काम हम उठा रहे हैं वह उसी क्षेत्र में हैं, लक्ष्य के लिए है, जिसमें नये-नये विचार, नयी-नयी तकनीक, नये-नये बीज, नयी-नयी पानी की पद्धति यह सब बातें उसमें हैं और उनको पूरा करके हम करना चाहते हैं और जो बॉयो फर्टिलाइजर की बात करते हैं, उसकी तरफ भी पूरा ध्यान है, क्योंकि मैं ज्यादा आर्टिफिसल फर्टिलाइजर पर नहीं रहना चाहता ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि अभी हाल ही में रिओ सम्मेलन में जो बॉयो-डाइवर्सिटी कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन में जीन बैंक के सवाल को बिलकुल अलग रखा गया है । मैं

मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि बैंक के सवाल को बिल्कुल अलग रखा गया है उससे भविष्य में विकासशील देशों को अनेक फसलों के बीजों को लेने में कई कठिनाइयां आएंगी। इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय के जहन में यह सवाल आया है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने पहले यह निर्णय ले लिया है कि वह उनको पेटेंट मोनोपली देने वाला है। तो इसका हमारे देश की फसलों पर क्या असर पड़ेगा... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Uniform Policy for conducting examinations by CBSE

*142. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that because of high rate of cheating, the Central Board of Secondary Education has introduced multiple sets of question papers for the Delhi Region for the last two years;

(b) if so, how far the new system has curbed cheating;

(c) what are the reasons for adopting different methods for different regions; and

(d) whether Government propose to introduce a uniform policy for all the regions, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (d) As a part of the efforts to eliminate mass copying and the use of unfair means, the Central Board of Secondary Education (CBSE), introduced multiple sets (four in number) of question papers for the first time in 1992 secondary (Class X) and Senior Secondary (Class XII) Examinations conducted by the Board in the Union Territory of Delhi.

With the introduction of multiple sets of question papers, the Board has succeeded in achieving the desired objective because there was not a single incident of mass copying in the Class X and Class XII Examinations conducted by the Board in Delhi in 1992, as against mass copying incidents reported in 20 examination centres of Delhi in 1991.

The reason for adopting multiple sets of question papers in Delhi was high incidence of mass copying in the CBSE Examinations in the Delhi centres in 1991. As the Board did not receive reports of mass copying in the 1991 Examinations conducted in other regions and foreign centres, use of multiple sets in 1992 Examinations outside Delhi was not introduced by the Board.

A Committee specially set up by the Board to review the impact of the system introduced in Delhi in 1992 recommended the uniform application of use of multiple sets of question papers in future Class X and Class XII Examinations in all the regions of the Board including the foreign centres. The recommendation has been approved by the Governing Body of the Board in its meeting held on 24-6-1992. The other Boards of Secondary/Higher Secondary Education of the country being autonomous bodies following their own independent examination and academic policies, are free to adopt or adopt this system as per their own discretion.

CBI enquiry into the losses suffered by the Food Corporation of India

*145. 145. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of FOOD be pleased to state: